

सरकार की कमाई में जोरदार उछाल

22% की बढ़ोतरी के साथ 2.08 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ

करदाताओं को 89,026 करोड़ का रिफंड जारी

नई दिल्ली, 19 जून चालू वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती ढाई महीनों में देश के प्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल से 17 जून 2026 के बीच नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.64 प्रतिशत बढ़कर 5.21 लाख करोड़ से अधिक हो गया है.

कर संग्रह में यह तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, बेहतर कॉर्पोरेट प्रदर्शन और कर अनुपालन में सुधार का संकेत मानी



सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है. केंद्रीय बजट में डायरेक्ट टैक्स से रुपए 26.97 लाख करोड़ जुटाने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के रुपए 23.40 लाख करोड़ के संग्रह की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है. वित्त वर्ष की शुरुआत में प्राप्त मजबूत कर संग्रह संकेत देते हैं कि सरकार अपने लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि उद्योगों की उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजन और उपभोक्ता मांग में मौजूदा सुधार जारी रहता है, तो आने वाले महीनों में कर संग्रह और मजबूत हो सकता है .

जा रही है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली. कंपनियों से प्राप्त नेट कॉर्पोरेट टैक्स राजस्व 22 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2.08 लाख करोड़ पहुंच गया. विशेषज्ञों का मानना है कि उद्योगों की बेहतर आय, निवेश गतिविधियों में वृद्धि और आर्थिक विस्तार के कारण कॉर्पोरेट क्षेत्र से कर संग्रह में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं से प्राप्त राजस्व में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई. नेट नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन करीब 8 प्रतिशत बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रहा. इस श्रेणी में व्यक्तिगत आयकरदाता, हिंदू अविभाजित परिवार , सझेदारी फर्में तथा अन्य गैर-कॉर्पोरेट इकायाें शामिल हैं.

आईपीओ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस मंजूर

मुंबई, 19 जून रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार इकाई जियो प्लेटफॉर्म के निदेशक मंडल ने कंपनी के आईपीओ के लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने यहां कंपनी की 49वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए बताया कि शुक्रवार को निदेशक मंडल ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की और आज ही इसे सेबी के पास जमा कराया जायेगा. इस आईपीओ प्रक्रिया का नेतृत्व ईशा, आकाश और अनंत अंबानी कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि एक समय था कि जब डाटा और वॉयस महंगा था और डाटा स्पीड कम था. जियो ने इस पूरे परिप्रिश्य को बदल दिया है.

भ्रामक दावों पर एफएसएसएआई की सख्ती

लेबलिंग, विज्ञापन और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

नई दिल्ली, 19 जून भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों और गलत लेबलिंग के मामलों में सख्त कदम उठाते हुए 14 खाद्य कंपनियों को नोटिस जारी किया है. एफएसएसएआई ने इन कंपनियों से जवाब मांगा है और उन्हें निर्देश दिया है कि वे अपनी गलतियों को सुधारें तथा खाद्य सुरक्षा और विज्ञापन से जुड़े सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करें.

एफएसएसएआई के अनुसार यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा वर्ष 2018 के विज्ञापन और लेबलिंग नियमों के तहत की गई है. जांच में पाया गया कि कई कंपनियां अपने



उत्पादों के प्रचार में ऐसे दावे कर रही थीं, जो उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि किसी भी खाद्य उत्पाद की पैकेजिंग और विज्ञापन

स्वच्छता और गुणवत्ता के मामलों में भी एफएसएसएआई ने सख्ती दिखाई है. 'बीकानेरवाला' को एक शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आरोप है कि रसोई क्षेत्र में कर्मचारी द्वारा भोजन किया जा रहा था, जो स्वच्छता नियमों के खिलाफ है. एफएसएसएआई ने कंपनी से इस मामले की जांच रिपोर्ट और सुधारात्मक कदमों की जानकारी मांगी है.



नौकरी छोड़कर शुरु किया ऑर्गेनिक फूड बिजनेस

रांची, 19 जून रांची के सूरज की कहानी आज उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है, जो सुरक्षित नौकरी छोड़कर खुद का व्यवसाय शुरू करने का साहस नहीं जुटा पाते.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद सूरज को एक बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस स्थिर करियर को छोड़कर अपने जुनून और स्वास्थ्य आधारित सोच को व्यवसाय का आधार बनाने का फैसला किया.

सूरज ने मखाना, किनुआ और चिया सीड्स जैसे ऑर्गेनिक और पोषण से भरपूर खाद्य उत्पादों को अपना व्यवसाय चुना. उनका मानना था कि आज के समय में लोग तेजी से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और प्राकृतिक

तथा पौष्टिक आहार की मांग बढ़ रही है. इसी सोच के साथ उन्होंने 'ऑर्गेनिक मंच' नाम से अपना ब्रांड शुरू किया.शुरुआत आसान नहीं थी. सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने स्कूटी से सामान ढोकर छोटे स्तर पर पैकेजिंग और बिक्री शुरू की. शुरुआती दौर में लोगों ने उनके इस निर्णय का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. धीरे-धीरे उन्होंने बिहार से मखाना, मध्य प्रदेश के किसानों से किनुआ और चिया सीड्स को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से लेना शुरू किया, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता बनी रही. सूरज का फोकस केवल बिक्री पर नहीं बल्कि गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर भी रहा. किनुआ को वे एक ऐसे सुपरफूड के रूप में पेश करते हैं, जिसमें कम कैलोरी और उच्च फाइबर पाया जाता है.

उनकी एक खास पहचान उनकी इको-फ्रेंडली पैकेजिंग भी है. वे प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते और हैंड पेंटेड तथा पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग पर जोर देते हैं, जिससे उनका ब्रांड पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है. समय के साथ उनके प्रयास रंग लाने लगे .आज उनका ब्रांड 'ऑर्गेनिक मंच' बड़े ई-कॉमर्स और विवेक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, जैसे क्लिकट, पर उपलब्ध है.

समाचार विशेष

मिशन 2027 के लिए मायावती का बड़ा दांव

जुलाई के अंत तक घोषित करेगी 100 से ज्यादा उम्मीदवार

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी कमर पूरी तरह कस ली है. बसपा अध्यक्ष मायावती के कड़े निर्देशों के बाद पार्टी ने अब अपने उम्मीदवारों के चयन की रफ्तार को काफी तेज कर दिया है. बसपा की योजना जुलाई महीने के अंत तक 100 से अधिक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने की है.

बसपा राजनीतिक गलियारे में एकमात्र ऐसी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने चुनाव से करीब 10 महीने पहले ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अब तक करीब 10 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम सहमति भी बन चुकी है. इस रणनीति का मुख्य मकसद



जनता के बीच उम्मीदवारों की पकड़ मजबूत करना है. मायावती के निर्देश पर अब सभी जिलों में संभावित उम्मीदवारों की मदद और जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. इन सम्मेलनों में बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हिस्सा लेंगे, ताकि कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया जा सके. पार्टी का

विरोधियों को बताया जातिवादी

मायावती ने अपने बयान में विरोधी राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें पूरी तरह जातिवादी और संकीर्ण मानसिकता वाला बताया. उन्होंने दावा किया कि विरोधी पार्टियों का रवैया हमेशा से ओबीसी समाज के प्रति बेहद खराब रहा है. इन पार्टियों ने राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के कारण ही कभी किसी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को आगे बढ़ाया है, जबकि ओबीसी समाज का असली हित और सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ बसपा के साथ ही संभव है .

मानना है कि इन सम्मेलनों की सफलता ही चुनाव में उनके टिकट के दावों को पुख्ता और मजबूत करेगी.

नवीन पटनायक से सीखें ममता

नई दिल्ली. ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से ममता बनर्जी को सीखना चाहिए. 79 साल के नवीन पटनायक न सिरे से शक्ति संचित कर रहे हैं और अपनी पार्टी को बचाने के साथ साथ उसे राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

गौरतलब है कि 2024 के चुनाव के बाद उनकी पार्टी में भी बिखराव हुआ है. हालांकि वैसा नहीं हुआ, जैसा ममता बनर्जी की पार्टी में हो रहा है. इसका कारण यह था कि ओडिशा के लोगों ने भले नवीन बाबू को हरा दिया था लेकिन लोग उनसे या

उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं से नफरत नहीं करते थे. कई जगह तो लोगों ने चुनाव नतीजों के बाद अफसोस जताया और कहा गया कि दोबारा चुनाव हो जाए तो फिर बीजू जनता दल जीत जाए. बहरहाल, पता नहीं तीन साल बाद होने वाले चुनाव में क्या होगा लेकिन उससे पहले नवीन पटनायक पूरी ताकत से सक्रिय हो गए हैं.

नवीन पटनायक ने अपने नेताओं के साथ बैठक की है. पहले तो वे अपने विधायकों से मिले. लेकिन उसके बाद वे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हारे हुए अपने प्रत्याशियों के साथ मिले.



इस वोट बैंक को साधने की कोशिश

कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस थर्ड फंट में आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम को भी शामिल कराना चाहते हैं. इसके पीछे उनकी मंशा है कि जनता के सामने एक तीसरा विकल्प दिया जाए. साथ ही दलित, पिछड़ा खासकर कोइरी समाज और मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करने की भी कोशिश है. चंद्रशेखर आजाद की थर्ड मोर्चे में एंट्री से दलित वोट बैंक को साधने में आसानी होगी, वही एआईएमआईएम की एंट्री से मुस्लिम वोट बैंक भी मोर्चे से जुड़ेगा .

कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के तीसरे मोर्चे में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो सकती है.

गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य करीब तीन दशक से यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं. लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें पड़रौना सीट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी

बनाया, लेकिन लगातार रामचरितमानस पर हमले के बाद सपा में भी कलह शुरू हो गई. इसके बाद 2024 में उन्होंने सपा एमएलसी पद दोनों से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद अपनी पार्टी बनाई.

राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने के बाद उन्होंने 9 छोटे दलों से गठबंधन कर लोक मोर्चा नाम से एक थर्ड फंट बनाया है.

सोशल मीडिया पोस्ट पर फंसे स्टालिन

चेन्नई. तमिलनाडु की विजय सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री आधव अर्जुन ने पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ तमिलनाडु राज्य की राजनीति में हलचल मची हुई है. डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन के घर अब लीगल नोटिस आ गया है. विजय की टीवीके सरकार आने के बाद आए दिन एमके स्टालिन का विवादित बयान सामने आ रहा है.

ऐसे में टीवीके मंत्री के खिलाफ एक बयान अब उन्हीं पर भारी पड़ गया है. यह पूरा मामला 8 जून को एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिस पर अब टीवीके मंत्री ने एक्शन ले लिया है. अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर एमके स्टालिन ने दावा किया था मंत्री आधव अर्जुन का ड्रा तस्करो के साथ संबंध है.

एमके स्टालिन ने लगाए आरोप- दरअसल, उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि, ईडी की एक प्रेस रिलीज के अनुसार, चेन्नई

सोशल मीडिया और टीवी पर प्रसारित करने की मांग

साथ ही स्टालिन और डीएमके की आईटी विंग को भेजे गए इस नोटिस में आधव अर्जुन ने कहा कि माफ़ी को सोशल मीडिया में शेयर करना होगा. साथ ही तमिल और अंग्रेजी अखबारों और टीवी चैनलों में प्रसारित भी करना होगा. आधव अर्जुन ने नोटिस में कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो वह उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे. बता दें, कि 8 जून को एमके स्टालिन ने ईडी की प्रेस रिलीज के हवाले से चेन्नई और रामनाथपुरम में जब्त किए गए 258 करोड़ रुपये के ड्रग तस्करी के मास्टरमाइंड जॉन ब्रिटो, आधव अर्जुन के करीबी रिश्तेदार होने का दावा किया था. इन दावों को आधव अर्जुन ने स्टालिन खारिज किया है.



और रामनाथपुरम में जब्त किए गए 258 करोड़ रुपये के ड्रग तस्करी के मास्टरमाइंड जॉन ब्रिटो, आधव अर्जुन के करीबी रिश्तेदार हैं. इस पोस्ट को लेकर अब एमके स्टालिन को लीगल नोटिस भेजा गया है. इसमें ड्रग तस्करी के मास्टरमाइंड जॉन ब्रिटो को रिश्तेदार बताने के लिए उन्हें बिना शर्त माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है. इतना ही नहीं बल्कि हर्जाने के रूप में 1 करोड़ रुपये देने की मांग भी की गई है. मंत्री आधव अर्जुन ने एमके स्टालिन को 48 घंटे का समय देते हुए सार्वजनिक माफ़ी मांगने को कहा है.